SME को इनोवेशन में मदद करेंगे IIT-IIM एक्सपर्ट

एनएमसीसी एसएमई की प्रबंधकीय क्षमता निखारने, क्वालिटी बढ़ाने में एक्सपर्ट की लेगी मदद

[अमित त्यागी *नई दिल्ली*]

नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपीटिटिवनेस काउंसिल (एनएमसीसी) ने एसएमई की प्रबंधकीय क्षमता निखारने, उत्पादों की क्वालिटी बढ़ाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी और आईआईएम के विशेषज्ञों की मदद लेगी।

एमएसएमई सेक्टर की मदद करने के लिहाज से आईआईटी और आईआईएम के विशेषज्ञ काफी मददगार साबित हो सकते हैं। एनएमसीसी के सेक्रेटरी जनरल अजय शंकर ने कहा, 'हम ऐसा सिस्टम तैयार करने पर विचार कर रहे हैं जिसमें देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षाविदों की मदद से एमएसएमई सेक्टर की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और इस क्षेत्र में इनोवेशन को रफ्तार दी जा सके।' फेडरेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (फिस्मे) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर (आईपीएफसी) की स्थापना की है। इस तरह के सेंटर बंगलुरु और हैदराबाद में पहले से काम कर रहे हैं।

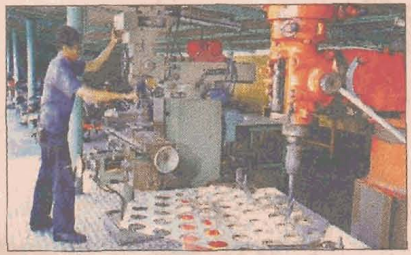

फिस्मे के प्रेसिडेंट वी के अग्रवाल ने कहा, 'फिस्मे द्वारा स्थापित आईपीएफसी केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निर्धारित सेवाओं के संचालन में मदद करेगा। इनमें पेटेंट और ट्रेडमार्क का पंजीकरण शामिल हैं। इसके अलावा यह आईपीएफसी आईपी ऑडिट, आईपी मैनेजमेंट सिस्टम्स और आईपी एक्सचेंज के रूप में एमएसएमई के लिए कंप्लीट बिजनेस मॉडल की तरह काम करेगा।' शंकर ने कहा कि आईपीएफसी की स्थापना के रूप में फिस्मे ने भारतीय एमएसएमई सेक्टर की तरक्की की राह में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने कहा, 'यह एमएसएमई सेक्टर के लिए लैंडमार्क है।' उन्होंने कहा कि नई निर्माण नीति के बाद देश के जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का हिस्सा बढ़कर 25 फीसदी तक पहुंच जाएगा और इसके लिए जरूरी है कि एमएसएमई सफलता के नए मानक स्थापित करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करें। जर्मनी का उदाहरण देते हुए शंकर ने कहा कि इनोवेशन से जर्मनी की कई एसएमई ने विश्व में अपनी दक्षता का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा, 'आज के दौर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और अगर इसे तकनीक की मदद मिल जाए तो देश के एमएसएमई में से भी कई एप्पल और क्वालकॉम जैसी कंपनियां सामने आ सकती हैं।'

अग्रवाल ने बताया कि फिस्मे के नई दिल्ली सेंटर में स्थित आईपीएफसी से दिल्ली-एनसीआर के ही नहीं, बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एमएसएमई भी फायदा उठा सकते हैं। आईपीएफसी में आईपी संबंधी जरूरतों के लिए विशेषज्ञों की पूरी टीम तैनात की जाएगी।